

मनरेगा से पशुआश्रय पाकर श्यामलाल यादव हुआ खुशहाल



प्राचीन काल से ही भारत की अर्थव्यवस्था की रीढ़ पशुपालन रहा है। चाहे वह दूध का मामला हो या फिर खेती के काम आने वाले बैलों का। वैदिक काल में दुधारु पशुओं की संख्या व्यक्ति की समृद्धि का मानक हुआ करती थी। सीधी जिले के संन्दर्भ में दुधारु पशु बहुत उपयोगी घरेलू पशुओं में गिने जाते हैं। ग्रामीण परिवारों का जीविका आधार दुधारु पशु ही रहे हैं। हर घर में गाय, बकरी, भैस की बहुतायत हुआ करती थी। दुधारु पशुओं को सुनिश्चित आवास से दुग्ध उत्पादन कर सुदृढ़ आजीविका की ओर कदम बढ़ाने के लिए महात्मा गाँधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना की उपयोजना पशुशेड निर्माण ने सम्बल प्रदान किया है। कहना न होगा की पशुशेड निर्माण से जिले में दुग्ध उत्पादन में वृद्धि संभव हो सकेगी।

इसी की एक नाजीर है जिले की जनपद सीधी की ग्राम पंचायत तेन्दुआ की विश्वकर्मा बस्ती में श्री श्यामलाल यादव पिता श्री रामगरीब यादव के यहाँ बनाया गया पशुशेड। व्यवस्थित पशुआश्रय पाकर श्री श्यामलाल अपनी आजीविका सुव्यवस्थित बनाने का प्रयास कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि दो भैस, दो गाय तथा दो बकरी के साथ उनके पास कुल नौ दुधारु पशु हैं। इन पशुओं की बदौलत वर्तमान में दस लीटर दूध होता है। शेष गौव से 40 लीटर दूध खरीदकर सीधी शहर में घर-घर ग्राहकों को पहुँचाते हैं। अपने इस व्यवसाय में लगभग 50 लीटर दूध रोज बेचकर वह महीने का 10 से 15 हजार रुपये की आय प्राप्त कर अपनी जीविका चला रहे हैं। पशुशेड मिलने के बाद अपने यहाँ दुधारु पशुओं की संख्या बढ़ाने की योजना है।

ग्राम सरपंच श्रीमती श्यामकली सेन ने बताया कि पशुशेड निर्माण दुधारु पशुओं को व्यवस्थित आश्रय देने की मनरेगा योजना की बहुउपयोगी उपयोजना है। इससे एक ओर दुधारु पशुओं से को आश्रय तथा दूसरी ओर खेती किसानों के लिए गोबर की खाद का उपयोग सुनिश्चित हो सकेगा। इन्हीं बातों को ध्यान में रखकर दूध का व्यवसाय कर आजीविका मजबूत करने के लिए श्री श्यामलाल यादव का चयन किया जाकर उनके यहाँ पशु आश्रय का निर्माण कराया गया है। अब पशु आश्रय पाकर उनके दुधारु पशु व्यवस्थित होकर दुग्ध उत्पादन को बढ़ाने का प्रयास का प्रयास श्री यादव द्वारा किया जा रहा है। उपयंत्री मनरेगा ने बताया कि वर्ष 214-15 में महात्मा गाँधी नरेगा की उपयोजना पशुशेड निर्माण के तहत कुल स्वीकृत राशि एक लाख चार हजार पर 99 मानव दिवस श्रजित कर 15 हजार 87 रुपये मजदूरी भुगतान किया गया है। कार्य में स्थानीय ग्रामीणों के साथ-साथ हितग्राही ने स्वयं तथा उनके पुत्र राहुल ने भी काम किया है तथा मजदूरी भुगतान पाया है। श्री श्यामलाल कहते हैं कि पशुआश्रय मिलने से उनकी आजीविका का आधार दुधारु पशुओं का आश्रय मिला है। इसका उपयोग कर वह अपनी आजीविका को और अधिक सम्बलता प्रदान कर रहे हैं।

कपिलधारा कूप से मिली सिंचित खेती और पेयजल व्यवस्था

खेती-किसानी करने के लिए पानी की आवश्यकता किसी से छिपी नहीं है। समय पर खेती को पर्याप्त सिंचाई मिल जाए तो पैदावार में दोगुनी वृद्धि निश्चित है। जिले में सिंचित खेती को महात्मा गांधी नरेगा की उपयोजना कपिलधारा कूप निर्माण ने सबल प्रदत्त किया है। बनाये गए कूप निर्माण से हितग्राही खेती की सिंचाई तो करते ही हैं साथ ही साथ में सब्जी भाजी उपजाकर अतिरिक्त आय भी प्राप्त कर रहे हैं। इसी की एक बानगी है जनपद पंचायत सीधी की ग्राम पंचायत खाम के राजभान सिंह गोंड जिन्होंने अपने खेतों की सिंचाई कर पैदावार तो बढ़ाई ही साथ ही साथ अपने कूप से आसपास के लोगों को भी सिंचाई का साधन उपलब्ध करा रहे हैं। श्री गोंड कहते हैं कि बिना सिंचाई के खेती में की गई मेहनत का पूरा फायदा नहीं मिल पाता। समय पर पानी की उपलब्धता होने पर सिंचाई कर दी जाती है, तो खेती लहलहा उठती है। कपिलधारा कूप के मिलने के बाद मेरी किस्मत भी लहलहा उठी है। इसी का परिणाम है कि मैंने खेती की अच्छी पैदावार प्राप्त की है। गुजरे सीजन में मैंने सिंचित खेती करके 25 क्विंटल धान और 30 क्विंटल गेहूँ की पैदावार प्राप्त की है। कूप निर्माण के पहले न तो कभी धान की खेती किया करते थे और न ही गेहूँ की इतनी बढ़िया पैदावार ही मिल पाती थी। कुए में ईश्वर की दया से बढ़िया पानी मिल गया है। बेतहासा पड़ती गर्मी में लोग पीने के लिए पानी भी इस कुए से ले जाते हैं। गांव में शादी ब्याह के लिए लोगों ने टैकर भरकर इसी कुए से पानी लिया है।

सरपंच **ग्राम पंचायत खाम** श्रीमती रामकली यादव ने बताया कि कपिलधारा योजना सिंचित खेती और पेयजल व्यवस्था को बेहतर कर रही है। कूप का फायदा लेकर हितग्राही सिंचित खेती से खेती को फायदे का सौदा बना रहे हैं। सचिव श्रीमती शिया दुलारी बताती है कि राजभान सिंह गोंड के यहाँ महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम-मध्यप्रदेश की उपयोजना कपिलधारा कूप निर्माण वर्ष 2011-12 में कराया गया है। कुल लागत 2 लाख 10 हजार रुपये है। कार्य में स्थानीय जॉबकार्डधारी परिवारों को 11 सौ 92 मानव दिवस श्रुजित कर रोजगार उपलब्ध कराया गया है। **राजभान सिंह गोंड** ने बताया कि अपनी खेती सींचने के बाद आस-पास के खेतों को सींचने के लिए पानी भी देते हैं। इसके एवज में उन्हें सालाना लगभग 6 से 8 हजार की अतिरिक्त आय भी प्राप्त हो जाती है। कपिलधारा कूप ने उन्हें आय का अतिरिक्त जरिया उपलब्ध कराया है।



कपिलधारा कूप ने दी रहिला की खेती किसानों से मुक्ति—विजय तिवारी



मेहनतकस को सुविधाएँ व अवसर मिले तो वह प्रगति के पथ पर चल पड़ता है। कुछ ऐसा ही प्रयास जनपद मझौली की ग्राम पंचायत टोगा के विजय तिवारी ने कर दिखाया है। श्री तिवारी बताते हैं कि सिंचाई के अभाव में खेती किसानों भगवान भरोसे ही चल रही थी। परिवार बड़ा हो तो आवश्यकताएँ और अधिक बढ़ जाती हैं। खेती के नाम रहिला ही पैदा हुआ करता था। कपिलधारा कूप बन जाने के बाद सिंचाई का साधन उपलब्ध हुआ। पहले वह अपने खेतों से ज्वार, कोदो, कुटकी तथा मक्का जैसे रहिला की पैदावार ही प्राप्त कर पाते थे। सिंचाई के आभाव में इन फसलों की पैदावार भी नाम मात्र की ही थी। कूप बन जाने के बाद गेहूँ 60 क्विंटल गेहूँ तथा लगभग 50 क्विंटल धान की पैदावार प्राप्त की है। खेतों में कटीले तार से फैंसिंग कराने के बाद सब्जी की पैदावार करने का मन भी बना रखा है।



उपयंत्री एस.एस. किरार ने बताया कि श्री तिवारी का परिवार गांव के मेहनती लोगों में जाना जाता है। महात्मा गांधी नरेंगा की पात्रता तथा कूप बनाने की सहमति के पश्चात ग्राम सभा से अनुमोदन कराकर कपिलधारा कूप का निर्माण कराया गया है। कूप का लाभ लेकर बढ़िया खेती कर विकास के पथ पर अग्रसर है। वित्तीय वर्ष 2012-13 में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम-म.प्र. की उपयोजना कपिलधारा कूप का निर्माण कराया गया है। कार्य की कुल लागत 2.66 तथा कार्य से श्रुजित मानव दिवस 986 रहा। हितग्राही के खेत में मेढ़ बंधान का कार्य भी कराया जाना प्रस्तावित है। ताकि खेतों की उर्वरा शक्ति बढ़े तथा मिट्टी के कटाव पर रोक लगाई जा सके।

मनरेगा की उपयोजना शान्तिधाम से पूरे हो रहे सामाजिक सरोकार

किसी ने ठीक ही कहा है कि जाएगा जब यहाँ से कुछ भी न पास होगा, दो गज कफन का टुकड़ा तेरा लिबास होगा। भागदौड़ भरी इस दुनिया में जीवन का आखरी सत्य यही है। इस अंतिम यात्रा के लिए भी आवश्यक सुविधाओं की दरकार अपेक्षित थी जिसे हम सामाजिक सरोकार सकते हैं। ऐसे ही सामाजिक सरोकार को पूरा कर रही महात्मा गाँधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना से शान्तिधाम का निर्माण एक अभिनव प्रयास के रूप में क्रियान्वित किया जा रहा है। इसी का प्रतिफल है कि महात्मा गाँधी नरेगा की उपयोजना से जीवन की अंतिम यात्रा शान्तिधाम (मुक्तिधाम) बनाये जाने से सुविधायुक्त मुक्तिधाम निर्मित किये जा सके हैं। जिले में मनरेगा की उपयोजना शान्तिधाम के तहत 76 स्वीकृत कार्यों में से 23 पूर्ण किये जा चुके हैं, शेष शान्तिधाम प्रगतिरित है। कराये जा रहे कार्यों में एक करोड़ सत्ताइस लाख आठ हजार रुपये व्यय किया जाकर जॉबकार्डधारी श्रमिकों को रोजगार की उपलब्धता भी सुनिश्चित की गई है।

इसी की एक नाजीर है सीधी जिले की जनपद सीधी की ग्राम पंचायत कठौली में मरघटिहा में बनाया गया शान्तिधाम जो अब सुव्यवस्थित हो गया है। रामकरण सिंह बताते हैं पहले शान्तिधाम इतना व्यवस्थित नहीं था। चारों तरफ बड़े गड्ढे तथा ऊबड़ खाबड़ होने के साथ अंतिम संस्कार करने के लिए चबूतरा व बैठक व्यवस्था नहीं होने के



कारण काफी परेशानी का सामना करना पड़ता था। अब शान्तिधाम को व्यवस्थित रूप दिया जा चुका है। अंतिम संस्कार के लिए चबूतरा, बैठक व्यवस्था तथा समतल भूमि होने से संस्कार कार्यक्रम सुविधा के साथ पूर्ण की जा रहे हैं। गाँव के बुजुर्ग श्री सीताशरण कहते हैं कि शान्तिधाम को व्यवस्थित करने का कार्य परोपकारी पुण्य कर्म है। शासन की योजना से ऐसे कार्य कराये जाने से सामाजिक सुविधाएँ बढ़ी हैं।

सहायक यंत्री मनरेगा जनपद सीधी श्री एस.एस.द्विवेदी बताते हैं कि उक्त शान्तिधाम मनरेगा की उपयोजना से 4 लाख 14 हजार रुपये की लागत से स्वीकृत किया गया है। शान्तिधाम निर्माण से स्थानीय ग्रामीण कठौली के अतिरिक्त आसपास के लोगों को भी इस सुविधा का लाभ मिलेगा। उपयंत्री श्रीमती सरिता सिंह ने बताया कि वर्तमान में शान्तिधाम का निर्माण कार्य में 2 लाख 78 हजार रुपये व्यय किये गए हैं। उक्त कार्य में 11 सौ 62 मानव दिवस सृजित किये जा चुके हैं। शेष कार्य कराया जा रहा है। ग्रामीण सुव्यवस्थित शान्तिधाम बनाये जाने के अनुभव को लेकर उत्सुक थे। अब उन्हें पहले की तरह अंतिम संस्कार करने में परेशानियों नहीं उठानी पड़ेगी। कहना न होगा कि महात्मा गाँधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना रोजगार के अधिकार और सामाजिक सरोकार के साथ ग्रामीण विकास का आधार बन गई है।

दुधारू पशुओं को मिला मनरेगा से व्यवस्थित आश्रय



प्राचीन काल में दुधारू पशु समृद्धि का प्रतीक माने जाते थे। युद्ध के दौरान स्वर्ण आभूषणों के साथ-साथ दुधारू पशुओं को भी लूट लिया जाता था। जिस राज्य में जितने अधिक दुधारू पशु होते थे वह उतना ही समृद्ध माना जाता था। भारत की अर्थव्यवस्था की रीढ़ पशुपालन रहा है। चाहे वह दूध का मामला हो या फिर खेती के काम आने वाले बैलों का। वैदिक काल में दुधारू पशुओं की संख्या व्यक्ति की समृद्धि का मानक हुआ करती थी। सीधी जिले में दुधारू पशु बहुत उपयोगी पशुओं में गिने जाते हैं। ग्रामीण परिवारों का जीविका आधार दुधारू पशु ही रहे हैं। सुदृढ़ आजीविका की ओर कदम बढ़ाने के लिए मनरेगा योजना की उपयोगिता पशुशेड निर्माण ने दुधारू पशुओं को सुनिश्चित आवास से दुग्ध उत्पादन कर सम्बल प्रदान करने का प्रयास किया है। इसी की एक नाजीर है जिले की जनपद सीधी की ग्राम पंचायत तेन्दुआ के श्री सवाईलाल पिता श्री सम्भूसिंह के यहाँ बनाया गया पशुआश्रय जहाँ अब उनके 09 दुधारू पशु व्यवस्थित रूप से आश्रय में हैं। श्री सवाईलाल ने कहा कि उनकी व्यक्तिगत रुचि दुधारू पशुओं को लेकर है। वह हमेशा अपने खेती के काम के साथ-साथ दुधारू पशुओं की सेवा करते आ रहे हैं। खेत से पर्याप्त मात्रा में पशुओं को चारा उपलब्ध हो जाता है। साथ-साथ ही साथ 12 से 15 लीटर दूध दैनिक रूप से गाँव के ही लोग घर से आकर खरीद ले जाते हैं। इससे 12 से 15 हजार की आय भी हो जाती है साथ में पशुओं की देखभाल तथा खुराक का खर्च भी समाहित है।

पशुशेड निर्माण दुधारू पशुओं को व्यवस्थित आश्रय देने की मनरेगा की बहुउपयोगी उपयोजना है। इससे एक ओर दुधारू पशुओं से आश्रय तथा दूसरी ओर खेती किसानी कार्य के लिए गोबर की खाद का उपयोग सुनिश्चित हो सका। इन्हीं बातों को ध्यान में रखकर दूध का व्यवसाय कर आजीविका मजबूत करने के लिए श्री सवाईलाल का चयन किया जाकर उनके यहाँ पशु आश्रय का निर्माण कराया गया। पशु आश्रय पाकर उनके दुधारू पशु व्यवस्थित होकर दुग्ध उत्पादन को बढ़ाने का प्रयास श्री सिंह द्वारा किया जा रहा है। वर्ष 2014-15 में महात्मा गाँधी नरेगा की उपयोजना पशुशेड निर्माण के तहत कुल स्वीकृत राशि एक लाख चार हजार की लागत राशि पर 99 मानव दिवस श्रजित कर 15 हजार 87 रुपये मजदूरी भुगतान किया गया है। कार्य में स्थानीय ग्रामीणों ने काम किया है। पशुआश्रय मिलने से पशुओं को व्यवस्थित रहने का ठिकाना मिला है। इनकी देखभाल से दूध उत्पादन से अतिरिक्त आय प्राप्त हो रही है।

मनरेगा से कटनी जिले में मिला 78 हजार परिवारों को रोजगार 27 लाख मानव दिवस हुये सृजित

मनरेगा ने साल में सौ दिन में काम की गारण्टी के साथ गांव के विकास में महति भूमिका निभायी है। कटनी जिले में वर्ष 2014-15 में मनरेगा के तहत 78 हजार परिवारों को काम दिया जिससे तकरीबन 27 लाख मानव दिवस सृजित हुये। वर्ष 2014-15 में 57 करोड़ 34 लाख रुपये से सामुदायिक भवन, ग्रेवल सड़क, तालाब, कन्ट्रेंच, कन्वरर्जेस से सीसी सड़क के कार्य कराये गये है। जिससे सीधे ग्रामीणजनों को लाभ पहुंचा है। इसी योजना में हितग्राही मूलक कार्यों में मवेसी सेट, कपिल धारा कूप, मेढ़ बंधान, कन्वरर्जेस से शौचालय का निर्माण किया गया है। जिससे संबंधित हितग्राहियों को लाभ मिला है। कपिल धारा कूप, मेढ़ बंधान से फसलों की उपज में वृद्धि हुई है। तेवरी के विकास में सहायक बनी मनरेगा विकास की एक कड़ी में ग्राम पंचायत तेवरी में महात्मा गांधी नरेगा योजना अन्तर्गत हितग्राही मूलक एवं सामुदायिक मूलक कार्य कराये गये है। जिससे ग्रामीणजनों को बेहतर सुविधा प्राप्त हुई है साथ ही हितग्राही मूलक कार्यों से हितग्राहियों की आर्थिक स्थिति भी पहले से बेहतर हुई है।

कटनी जिले की ग्राम पंचायत तेवरी में 10 कार्यों पर लगभग 31 लाख 86 हजार रुपये व्यय किये गये है। यह राशि महात्मा गांधी नरेगा योजना अन्तर्गत व्यय की गई है। तालाब निर्माण तेवरी पर 4 लाख 34 हजार रुपये मुरम मिट्टी मार्ग तालाब से हडौंडी के खेत तक निर्माण कराया गया। जिस पर 3 लाख 29 हजार रुपये कंटूर ट्रेन्च, लेहमिहर बटिया में 3 लाख 62 हजार रुपये लगभग व्यय किये गये।

इस पंचायत में लीला सिंह के खेत में समतलीकरण का कार्य पर 45 हजार रुपये, शमशेर सिंह के खेत में समतलीकरण कार्य पर 39 हजार रुपये लगभग व्यय किये गये। शंकर जी की भटिया में वृक्षारोपण कार्य पर 4 लाख 51 हजार रुपये मस्तान शाह से मिलन ढोल तक सीसी रोड के निर्माण पर 4 लाख 36 हजार रुपये, बरहां कुआं से पावर हाउस तक सीसी सड़क निर्माण पर 4 लाख 94 हजार रुपये, बद्री ढोल से दशरथ कुम्हार तक सीसी सड़क निर्माण पर 3 लाख 47 हजार रुपये, कैलाश के घर से अनुरुद्ध के घर तक सीसी सड़क निर्माण पर 2 लाख 45 हजार रुपये लगभग व्यय किये गये। इन कामों से तेवरी पंचायत के निर्माण कार्यों में तालाब निर्माण से क्षेत्र में ग्रामीणजनो को पानी की सुविधा उपलब्ध हो सकी है। यह पानी ग्रामीणजनो द्वारा निस्तार हेतु उपयोग किया जा रहा है। वर्षा के पानी को रोकने व तालाब में घाट निर्माण से व्यक्ति को पानी व पानी के उपयोग विभिन्न स्त्रोतों में करने हेतु मिली है। तालाब निर्माण से लगभग 50 से अधिक परिवार को पानी की कमी से निजात मिला है।

आवागमन की सुविधा

तेवरी पंचायत में मिट्टी मुरम मार्ग से दो गांवों को जोड़ने के लिये रास्ते का निर्माण किया गया है। पूर्व में यह पगडंडी जैसा रास्ता था। जिससे कृषको एवं ग्रामीणजनों को आने जाने में असुविधा होती थी। इस रास्ते के निर्माण से ग्राम विछुआ व सलैयाप्यासी तक जाने में सुविधा हुई है। इससे लगभग 100 कृषकों को खेती का सामान ले जाने भी सुविधा मुहैया हो सकी है। वहीं कृषकों के यहा खेत में

समतलीकरण कार्य से उबड़-खाबड़ जमीन को खेती योग्य बनाया गया है। जिससे कृषको की कृषि उपज में वृद्धि हुई है। ग्राम पंचायत तेवरी में चार सीसी सड़क निर्माण कार्य से आस-पास के ग्रामीण जनो को एक बेहतर मार्ग प्राप्त हुआ है। जिससे बारिस में कीचड़ होने, जैसी समस्याओं से निजात मिली है। कन्टूर ट्रेन्च के निर्माण से उक्त क्षेत्र में जल संवर्धन का कार्य किया गया है। ग्राम पंचायत तेवरी में उक्त कार्यों के हो जाने से तेवरी के ग्रामीण जनो को सड़क, पानी तथा कृषि उपज में वृद्धि जैसी सुविधा प्राप्त हुई है। इन 10 कार्यों पर लगभग 31 लाख 86 हजार रुपये की राशि व्यय हुई है।



कपिलधारा ने बदली गरीब किसानों की तकदीर दो से अधिक फसल लेना हुआ आसान



देवास जिले में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजनांतर्गत हो रहे विभिन्न कार्यों से यहां के लोगों की जिंदगी में काफी बदलाव आया है। रोजगार के लिए लोगों का गांव से शहर की ओर पलायन रुका है। कृषि उत्पादन में भी वृद्धि हुई है। जिससे लोगों की आर्थिक, सामाजिक स्थिति सुदृढ़ हुई है। देवास विकासखण्ड के सेरगोना के सरपंच ने बताया कि यहां रोजगार गारंटी योजना से लोगों की जिंदगी में सकारात्मक परिवर्तन आया है। पहले जो लोग जीवनयापन के लिए मजदूरी करते थे अब वो खुद अपनी खेती करने लगे हैं। उन्होंने बताया कि उनकी ग्राम पंचायत में राम सिंह पिता बलराम, छतरसिंह पिता बलराम के यहाँ कपिलधारा कूप का निर्माण हुआ है। उनके खेत हरे-भरे हो गये हैं। जिससे उनकी जिंदगी खुशहाल हो गई है।

पहले जब पानी की समस्या थी तो अपने खेत होते हुए भी उन्हें जीवनयापन/मजदूरी के लिए अन्यत्र जाना पड़ता था। बारिश के पानी से जो वर्ष में 1 मात्र फसल होती थी उससे पूरे परिवार का जीवनयापन किसी भी तरह से संभव नहीं था। आर्थिक हालात कमजोर होने की वजह से पानी की व्यवस्था के लिए कुआं बनाने का सोंचा भी नहीं जा सकता था। आर्थिक हालात कमजोर होने की वजह से किसानों की जिंदगी बिखरने लगी थी।

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना अंतर्गत आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों को कपिलधारा कूप उपयोजना अंतर्गत कूप स्वीकृत किये जाते हैं। जिसमें निर्माण कार्य में कार्य करने पर मजदूरी भी योजना अंतर्गत प्रदान की जाती है। निर्माण कार्य में राम सिंह एवं छतरसिंह के परिवार ने कार्य किया जिसकी मजदूरी उन्हें अलग से योजना अंतर्गत दी गई। कुएं बने तो पानी की समस्या का समाधान हो गया। और खेती की लय पुनः लौट आई। जिससे खेतों के साथ जीवन भी हरा-भरा हो गया।

विवादों पर विराम लगाती विकास की सड़क पंच परमेश्वर मार्ग बनने से दूर हुए आपसी गिले शिकवे

जिला मुख्यालय से 15 कि.मी. दूर बसी है छैगांवमाखन जनपद की ग्राम पंचायत सुरगांवजोशी। इस ग्राम पंचायत की विडंबना थी कि यहां लोगो के पास पर्याप्त पैसा होने पर भी पंचायत में विकास की धुरी ठहरी हुयी थी, कारण था लोगो में आपसी मन मुटाव होना। ग्राम पंचायत में विकास कम, विवाद ज्यादा थे गांव में पक्की बिलडिंगे तो बनी थी परंतु गांव की गलियां कच्ची व कीचड़ से सराबोर थी। पंचों के आपस में विवाद होने के कारण पंचायत की बैठकें भी बहुत ही कम हो पाती थी। इस पंचायत में ग्रामीणों द्वारा आपसी रंजिश के चलते 13 स्थानों पर शिकायतें दर्ज करवा रखी थी। जिस समय पंचायत में विकास गर्त में जाने लगा था उसी समय प्रदेश शासन की महत्वाकांक्षी योजना पंचपरमेश्वर प्रारंभ हुयी एवं अन्य पंचायतों की भांति ही सुरगांवजोशी पंचायत में भी पंचपरमेश्वर अंतर्गत सीमेंट कांक्रीट मार्ग के निर्माण की स्वीकृतियां जारी की गई। सुरगांवजोशी के लोगो के लिये यह पहला अवसर था जब उनके गांव में पक्की सड़क बन रही थी। लोगो मे आपसी समन्वय न होने के कारण गांव की लगभग 25 गलियां गंदगी का घर बनकर बीमारियों को पनाह दे रही थी। पंचपरमेश्वर योजना अंतर्गत आस-पास की ग्राम पंचायतों में बने पक्के मार्गों को देखकर सुरगांवजोशी के लोगो ने भी इस योजना से अपने गांव की गंदगी को दूर कर विकास के मार्ग का निर्माण करने की मन में ठान ली थी।



पंचपरमेश्वर योजना और मनरेगा योजना के समन्वय द्वारा सुरगांवजोशी में 4.02 लाख रु की लागत से पक्के मार्ग का निर्माण किया जाना तय हुआ और पहले मार्ग निर्माण के लिए जगदीश चम्पालाल से नथू की दुकान की प्रशासकीय स्वीकृति जारी की गई। यह गांव की वह गली थी जो ढलान में बनी थी ओर गांव के घरों से निकलने वाला अधिकांश निस्तारी पानी इसी गली में से बहता था अतः यह गली एक गटर का रूप ले चुकी थी। नथू पिता श्यामलाल बताते हैं कि इस गली की गंदगी के चलते उनकी किराना दुकान पर व्यवसाय बहुत कम हो पाता था परंतु अब पक्की सड़क बन जाने से ग्राहकी में दोगुनी वृद्धि हो गयी है। मनरेगा के समन्वय से बने पंचपरमेश्वर योजना के एक पक्के मार्ग से सुरगांवजोशी के लगभग 100 परिवारों को नरकीय जीवन से मुक्ति मिल गयी है।

सुरगांवजोशी में बने पंचपरमेश्वर के पक्के मार्ग ने वहां के निवासियों के विचारों में भी परिवर्तन कर दिया है गांव के श्री चंद्रशेखर पटेल बताते हैं कि गांव के लोग इस विकास कार्य से इतना प्रभावित हुए हैं कि सभी लोगो द्वारा अपनी शिकायतें वापिस ले ली गई हैं और अब सभी लोग गांव में विवाद की जगह विकास चाहते हैं लोगो का तो यहां तक कहना है कि यदी पंचपरमेश्वर से बने मार्ग जैसा मार्ग गांव में कभी पहले बन जाता तो शायद गांव के लोग आपसी रंजिश को भुलाकर विकास के नवीन सोपानो की ओर बढ़ गये होते।

खण्डवा जिले में पंचपरमेश्वर योजनांतर्गत 2158 कार्य स्वीकृत किये गये हैं जिनमे से माह मार्च 2015 तक 1570 कार्य पूर्ण किये गये हैं। पूर्ण कार्यों के द्वारा जिले में 160.84 कि.मी. लंबाई के मार्गों का निर्माण कराया गया है। योजनांतर्गत 7446.55 लाख रु की राशि स्वीकृत की जाकर पूर्ण कार्यों पर 6329.6 लाख रु व्यय किये गये हैं। मनरेगा अंतर्गत 1912.72 लाख रु राशि पंच परमेश्वर मार्गों के निर्माण पर व्यय की गयी है।